

संपादकीय

सरकार विरोधी मोर्चा की संभावना

प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की विपक्षी नेताओं से मुलाकात के कारण चुनाव पूर्व सरकार विरोधी मोर्चा की संभावना को बल मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इससे आंश्र प्रदेश में दोनों पार्टीयों के बीच गठबंधन और कांग्रेस के अन्य दलों के साथ आने का रास्ता निकल सकता है। राहुल से मुलाकात के पहले नायडू मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलश यादव, शरद पवार, फारुक के अब्दुल्ला से मिल चुके हैं। इस तरह वे एक कड़ी की भूमिका में इस समय दिख रहे हैं। राहुल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग पुरानी बातों को भूलकर देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ काम करेंगे। हालांकि राहुल की बातों में नया कुछ नहीं था, लेकिन मिलने और साथ आकर मीडिया से बात करने के कारण गोलबंदी का एक वातावरण बनते हुए तो दिखता ही है। बाद में अब्दुल्ला और पवार के साथ पत्रकारों से बातें करते हुए भी उसी पर जोर दिया गया। पवार ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तक की बात कह दी। मीडिया से हुई इन दोनों बातों से यह तो साफ हो गया कि ये सरकार के विरुद्ध प्रमुख संस्थाओं की आजादी पर हमला कर लोकतंत्र को नष्ट करने और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। नायडू ने “सेव नेशन सेव डेमोक्रेसी” का नारा भी दिया। जैसा पवार ने कहा कि योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसका मतलब हुआ कि इन मुलाकातों के दौर खत्म होने के बाद नायडू इन नेताओं को एक साथ बिटाएंगे। जितने नेता एक साथ आएंगे उनसे ये यह दावा कर सकेंगे कि हम मोदी सरकार एवं भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं और गठबंधन की दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी इन कवायदों से बड़ा निष्कर्ष निकाल लेना जल्दबाजी होगा। सभी राज्यों और वहाँ के प्रमुख दलों की अपनी सियासी आकांक्षाएं और जमीनी वास्तविकताओं की किसी भी गठबंधन में प्रमुख भूमिका होती है। बावजूद इसके इन कवायदों के संभावित राजनीतिक प्रभावों को खारिज नहीं किया जा सकता है। चुनाव पूर्व गठबंधन में जितनी सफलता मिलेगी वह अपनी जगह है ही। अगर परिणाम बाद ऐसी स्थिति आई, जिसमें भाजपा या राजग को बहुमत नहीं मिला तब चंद्रबाबू नायडू की केंद्रीय भूमिका के कारण एक मोर्चा बन सकता है।

सूचना प्रशासन

जम्मू संभाग के किशतवार इलाके में भाजपा के प्रदेश सचिव एवं उनके भाई की आतंकवादियों द्वारा हत्या ने एक साथ कई भयानक संकेत दिए हैं। इस आतंकवादी वारदात का आरोप लश्कर-ए-तैयबा पर लगाया गया है। किशतवार के इलाकों में काफी समय से कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। इस हमले का अर्थ है कि आतंकवादी उस क्षेत्र में आ चुके हैं। आगामी 19 नवम्बर के पंचायत चुनाव को देखते हुए वहां और भी हमले की योजना वे बना रह होंगे। पहला संकेत तो यही है कि आतंकवादी पंचायत चुनाव को हर हाल में विफल करना चाहते हैं। इसके पहले नगर निकायों के चुनावों में पूरे जम्मू संभाग में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया और उसमें भाजपा को काफी सफलता मिली। यह बिल्कुल संभव कि प्रदेश के एक बड़े भाजपा नेता का अंत कर वे भाजपा समर्थकों के साथ मतदाताओं को भी भयभीत करना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश सचिव अनिल परिहार इसके पूर्व स्थानीय चुनावों में काफी सक्रिय थे। घाटी में भी पार्टी ने उनको भेजा था। वहां भी चुनाव में उन्होंने काम किया था। इस कारण भी आतंकवादियों की उन पर नजर रही होगी। जैसा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कुछ दिनों पहले खुफिया के एक अधिकारी उनसे मिलने आए थे, जिन्होंने बताया था कि आतंकवादी भाजपा के नेताओं को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। यह सूचना प्रशासन को बिल्कुल रही होगी। इस समय प्रदेश राज्यपाल शासन में है इसलिए राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति नहीं है। किंतु किसी भी स्थिति में आतंकवादियों के इरादों को सफल न होने देना ही इसका करारा प्रत्युत्तर है। पंचायत चुनावों में भारी संख्या में मतदान कर उनको जताया जा सकता है कि आतंकवादी हमलों से डरकर लोग पीछे नहीं हटने वाले। सुरक्षा की जितनी संभव व्यवस्था हो की जानी चाहिए ताकि लोग निर्भय होकर मतदान कर सकें। बावजूद इसके यह घटना बताती है कि आतंकवाद के संघर्ष में अभी अनेक लोगों को अपने या परिजनों की बलि चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। यही जज्बा आतंकवाद को परास्त करेगा। आतंकवादियों को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वे अपनी बंदूकों के बल पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला ढोंटने के अपने गंदे लक्ष्यों में सफल नहीं हो सकते।

सत्संग

मन

कल्पना कामना नहीं है, मात्र एक खेल है। कामना तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन तुम अपनी कल्पना को कामना पर आधारित कर सकते हो, तुम अपनी कामना को कल्पना द्वारा प्रक्षेपित कर सकते हो, तब वह बंधन हो जाएगी। यदि तुम कल्पना के साथ बिना किसी कामना के खेलते हो-न कहीं पहुँचने के लिए, न कुछ पाने के लिए, बस एक खेल की तरह उसे लेते हो-तब तुम्हारी कल्पना न कामना होती है, न बंधन। कल्पना की ये विधियां केवल तभी सहयोगी हो सकती हैं यदि तुम उनके साथ खेलो। यदि तुम गंभीर हो गए तो सारी बात ही चूक गए। लेकिन प्रश्न संगत है। क्योंकि वास्तव में, तुम सोची ही नहीं सकते कि बिना कामना के कुछ किया जा सकता है। तुम तो अगर खेलते भी हो तो कहीं पहुँचने के लिए, कुछ पाने के लिए, जीतने के लिए। यदि भविष्य में कुछ भी मिलने वाला न हो तो तुम्हारा सारा रस खो जाएगा। तुम कहोगे, “पिछे खेलें ही क्यों?” हम इतने परिणाम-उन्मुख हैं कि हर चीज को साधन बना लेते हैं। इसे स्मरण रखना चाहिए: ध्यान तो परम लीला है, कुछ पाने के लिए, साधन नहीं है, ध्यान बुद्धत्व पाने के लिए साधन नहीं है। ध्यान से बुद्धत्व घटता है, लेकिन ध्यान उसके लिए साधन नहीं है। न ही ध्यान मोक्ष के लिए साधन है। मोक्ष उससे घटता है, लेकिन ध्यान उस के लिए साधन नहीं है। तुम ध्यान का किसी फल की प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं कर सकते। यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिन्होंने भी जाना है, वे सदियों से ध्यान के लिए ही ध्यान करने पर जोर देते रहे हैं। उससे कुछ पाने की कामना मत करो, उसका आनंद लो, उससे बाहर कोई लक्ष्य मत बनाओ-और बुद्धत्व उसका परिणाम होगा। स्मरण रखो, परिणाम, फल नहीं। ध्यान कोई कारण नहीं है, लेकिन ध्यान में तुम गढ़े डूबते हो तो बुद्धत्व घट जाता है। असल में, इस खेल में गहरे डूब जाना ही बुद्धत्व है। लेकिन मन हर चीज को कार्य बना लेता है। मन कहता है, कुछ करो क्योंकि उससे यह लाभ होगा। काल्पनिक या वास्तविक, मन को कुछ चाहिए जिससे सहारा मिल सके, जिसे मन प्रक्षेपित कर सके। केवल तभी मन चल सकता है। मन भविष्य के लिए वर्तमान में काम करता है। भविष्य चाहे काल्पनिक ही हो, चाहे कभी आए ही न, लेकिन मन केवल भविष्य की आश में ही काम कर सकता है। भविष्य के लिए वर्तमान में काम करने को ही कामना कहते हैं।

“માઉંટબેટેન પ્લાન”

कश्मीर के महाराजा, हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब द्वारा अब तक किसी भी संघ में विलय नहीं किया गया था। हरि सिंह द्वारा अब तक भारत में शामिल नहीं होने के निर्णय से आशंका यह भी बन रही थी कि वह पाकिस्तान में भी विलय चाहते हों। प्रांतीय सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ “स्टैंड स्टील एग्रीमेंट” के बाद ऐसे कहास और तेज होने लगे थे। बिटिश भारतीय शासन द्वारा तैयार किए गए इस एग्रीमेंट के तहत रियासतों द्वारा किसी भी संघ में विलय की अवधि तक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हूबहू लागू रखने का प्रावधान था, जिसे भारत ने ठुकरा दिया और पाकिस्तान ने बिना कोई देरी किए स्वीकार कर लिया।

पाकिस्तान ने बिना कोई देरी किए स्वीकार कर लिया

सतीश पेडणोकर



कि जून 1946 में उन्हें रिहा कराने के लिए नेहरू ने कश्मीर जाने की घोषणा कर दी थी। कुल मिलाकर, भारत की धर्मनिरपेक्षता, कश्मीरियत में नेहरू और शेख अब्दुल्ला का विस और अंततः हरि सिंह की मजबूरी के बीच जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ का अंग बन गया। अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संसद को सिफरक्षा, विदेश मामले और संचार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त रहा है। इसकी आत्मा कही जाने वाली धारा 35ए वहाँ के नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। मसले की नाजुकता के बावजूद आए दिन धारा 370 को समाप्त करने की राजनीतिक वकालत होती रही है। देश के एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान प्रशंसनीय हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन की प्रस्तावित योजना के तहत पूरा बंगाल, पंजाब और असम पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा था। दूरदर्शी पटेल ने रोध करते हुए कहा, “यह प्रस्ताव तो भी ज्यादा खराब है।” बाद में एक बार एटली नीति के तहत पंजाब, बंगाल और असम का प्रस्ताव रखा गया। दोबारा लाए राते हुए पटेल ने पंजाब और बंगाल के देया और पूरा असम भारत का हिस्सा। 15 अगस्त 1947 को अपनी हठधर्मिता या होता तो समस्या पैदा ही नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने जैसी कवायद 31 अक्टूबर को लौह पुरुष की जयंती के संकल्पों की याद दिलाता है।

चलते चलते

ऑफ इंग बिजनस

रुपया और गिर गया उ. ईंज ऑफ इंग बिजनस में देश ऊपर भी तो उठ पाया। प्र. डालर 74 रुपये का हो गया। यह इतना नीचे कभी नहीं गिरा था ? उन आँफ दुइंग बिजनस में इंडिया 73 स्थान तक भी तो कभी नहीं चढ़ा था तो क्या रुपया यों ही गिरता रहेगा और सरकार कुछ नहीं करेगी ? उ. ईंज ऑफ इंग बिजनस में देश ऊपर चढ़ता है, इसके लिए सरकार कोई कसर नहीं देंगी। प्र. और क्या सरकार रिजर्व के से यों ही लड़ती रहेगी ? उ. कहा न रकार कुछ भी करेगी। प्र. उसके लिए जर्व बैंक मे लदना क्या ज़रूरी है ?

उ.दुनिया के आगे देश की इज्जत सवाल है। देश की इज्जत बढ़ाने के स्तरे में कोई भी आए, यह सरकार गर्ज बर्दाश्त नहीं करेगी। प्र.पर बेचारा

वया रूपया याँ ही गिरता रहेगा
और सरकार कुछ नहीं करेगी ? त.
ईज ऑफबुइंग बिजनेस में देश ऊपर
चढ़ता रहे, इसके लिए सरकार कोई
कर्सर नहीं ठोड़ेगी। प्र. और वया सरकार
रिजर्व बैंक से याँ ही लड़ती रहेगी ?
ठ. कहा न सरकार कुछ भी करेगी।
प्र. उसके लिए रिजर्व बैंक से लड़ना
वया जरूरी है ? ठ. दुनिया के आगे देश
की इज्जत का सवाल है। देश की
इज्जत बढ़ाने के रास्ते में कोई भी
आए, यह सरकार हर्गिज बर्दाश्त
नहीं करेगी।

रिजर्व बैंक ईज आफडुइंग बिजनस में कैसे आड़े आ रहा है ? उ.बेचारा होता तो डुइंग बिजनस को आसान बनाने में सरकर की मदद करता ? प्र.पर वह तो डुबाऊ करजे की बाढ़ पर अंकुश लगाने की और डबने से बैंकों को बचाने की कोशिश

कर रहा है ? उ.पर कर क्या रहा है ? डूबने वे डर से और कर्जा देने से इनकार। प्र.पर जो पहले कर्जा मारे बैठे हैं, उन्हें और कर्जा देकर बैंक खुद क्यों डूब जाएं ? उ.बैंक खुद ही अगर डूबने से डरेंगे तो ईज ऑफ डुइगा बिजनस कैसे बढ़ेगा ? प्र.पर यह कैसा ईज आप डुइंग बिजनस हुआ ? यह तो ईज ऑफ लटिंग हुआ ?

उत्तर : डॉ. बिजनस सरकार ने इंडिया एक्सप्रेस की विवादों का अधिकारी बनाया है। उन्होंने अपने अधिकारी के रूप में इसकी विवादों का अधिकारी बनाया है।

फोटोग्राफी...



हर्वे टिली में बहते पटाका के बीच शक्ति सबह लोधी गार्डन में बैठे हो रहे।

पीड़ितों को “इंसाफ़”

शिमपुरा नरसंहार मामले में पीड़ितों को आखिरकार “इंसाफ” मिल गया है। इस नृशंस नरसंहार के गुनहगारों को इकतीस साल बाद ही सही अपने किए की सजा मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इस चर्चित मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए प्रेविंशियल आर्ड कॉन्स्टेबलरी यानी पीएसी के 16 रिटायर जवानों को उपक्रैद की सजा सुनाई है। जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की पीड़ित ने पीएसी के जवानों को हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया। अदालत का इस बारे में कहना था कि सभी के खिलाफ मजबूत ठोस सबूत हैं। यह सीधे-सीधे हिरासत में मौत का मामला है। इस मामले में पीएसी जवानों ने मानवाधिकार का हनन किया है। न्यायपालिका से संबंधित प्रचलित धारणा है कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं कहलाता। पिछे इस मामले में, तो इंसाफ मिलने में पूरे इकतीस साल लगे। इस दौरान नरसंहार के तीन मुजरिम, बिना सजा पाए अपनी मौत मर गए। वहीं पीड़ितों ने इंसाफ पाने के लिए क्या-क्या नहीं झेला। पीड़ित तमाम दबाव झेलते रहे, लेकिन अपने इरादे से नहीं डिगे। अदालत के इस फैसले से पीड़ितों के अपने वापस तो नहीं आ सकेंगे, पर उनके जख्मों पर कुछ मरहम जरूर लगेगा। वर्दी की आड़ में जो लोग, मजलूमों पर जल्म-ओ-सितम ढाते हैं, उन्हें डर रहेगा कि यदि उन्होंने कुछ गलत किया, तो कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा। कभी-न-कभी उन्हें अपने किये की सजा जरूर मिलेगी। “हाशिमपुरा नरसंहार” नाम से पहचाने जाने वाला यह दर्दनाक मामला, साल 1987 के 22-23 मई की दरमियानी रात का है। उस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका साम्प्रदायिक दंगों में झुलस रहा था। मेरठ जिले के हाशिमपुरा गांव में अचानक पीएसी के जवान आए और एक सधा से अल्पसंख्यक समुदाय के 42 से 45 नौजवानों को ट्रक में भरकर अपने साथ ले गए। बाद में पीएसी के जवानों ने ट्रक में सवार लोगों को मुरादनगर गंगनहर पर ले गए और उन्हें गोलियों से भून दिया। बाद में उनकी लाशों को नहर में फेंक दिया। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह बहुत तकलीफद्देह है कि कुछ बेगुनाह लोगों को इतनी यंत्रणा झेलनी पड़ी और एक सरकारी एजेंसी ने उनकी जानें लीं। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने अफसोस भरे लहजे में कहा, जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष दोषियों की पहचान को साबित करने लायक सबूत पेश करने में नाकाम रहा। लिहाजा मौजूदा परिस्थितियों में सभी 16 अभियुक्तों को उन पर लगाए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। निचली अदालत द्वारा हत्या और अन्य अपराधों के आरोपित 16 पूर्व पुलिसकर्मियों को बरी करने के फैसले से पीड़ित परिवार, जरा सी भी हिम्मत नहीं हरे। पीड़ित परिवारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार और दीगर लोगों ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जहां अदालत ने आखिरकार पीड़ितों के हक में इंसाफ सुनाया। हाशिमपुरा मामले में गुनहगार खुद पुलिस थी, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने ही अपने मातहतों को बचाने का काम किया। इस मामले के ज्यादातर सबूतों को दबाया गया या नष्ट कर दिया गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभियुक्त पुलिसवालों को कभी भी निलंबित नहीं किया गया। होना तो यह चाहिए कि जो इस अपराध के सहभागी या आपराधिक लापरवाही के दोषी हैं, उनकी भी इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाए और उन्हें उनके किए की उचित सजा मिले। तभी इस मामले में पीड़ितों को सही इंसाफ मिलेगा।

